

(11)

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band -2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :
- (i) Master's Degree in Geography from a recognised University; and
- (ii) three years' research or teaching experience in the field of Cartography including Economic Geography or Population Geography in a recognised Institute.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st, January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Not applicable

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-51011/2/2008-Ad. V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट भर्ती नियम, 2010 में—

(क) नियम 1 में, उप-नियम (1) में, अंक "2010" को अंक "2011" से प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) अनुसूची में, कालम (2) में, कोष्ठकों और अंक "(2010)" को कोष्ठक और अंक "(2011)" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. ए-16011/5/2000-प्रशा. II/V]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. सं. 1 दिनांक 1 जनवरी, 2011 के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि. सं. 93 दिनांक 19 मार्च, 2011 के अनुसार संशोधित किए गए।

New Delhi, the 17th February, 2012

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Offices of the Registrar General, India, and the Office of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Offices of the Registrar General, India and the Office of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Offices of the Registrar General, India, and the Office of the Director of Census Operations in States and the Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010,—

(a) in rule 1, in sub rule (1), for the figures "2010", the figures "2011" shall be substituted;

(b) in the Schedule, in column (2), for the brackets and figures "(2010)", the brackets and figures "(2011)" shall be substituted;

[F. No. A-16011/5/2000-Ad. II/V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 1, dated the 1st January, 2011 and subsequently amended vide GSR No. 93, dated the 19th March, 2011.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।